मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 3 जून 2021

एमसीआईआर

I. मौद्रिक नीति

एमपीसी का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 4 जून 2021 को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

मौद्रिक नीति समिति ने यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

चलनिधि उपाय

❑ संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप चलनिधि विंडो – देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2022 तक रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि विंडो प्रारंभ करना। यह भी निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2022 तक रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ ₹15,000 करोड़ की एक अलग चलनिधि विंडो, कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया जाए।

❑ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विशेष चलनिधि सुविधा- छोटे एमएसएमई और व्यवसायों जो ऋण की कमी और आकांक्षी जिलों में है, पर अतिरिक्त ध्यान देने के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लघु और मध्यम अवधि की ऋण जरूरतों के निवेश चक्र शुरू करने के लिए सिडबी को ₹6,000 करोड़ की एक और विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

विनियमन और पर्यवेक्षण

❑ समाधान ढांचा 2.0 के तहत एक्सपोजर सीमा का संवर्धन- 5 मई 2021 को रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित समाधान ढांचा 2.0 में एमएसएमई के साथ-साथ गैर-एमएसएमई छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित तनाव और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ऋण के समाधान पर विचार करने के लिए ₹25 करोड़ का अधिकतम कुल एक्सपोजर निर्धारित किया गया। उपरोक्त एक्सपोजर सीमा को बढ़ाकर ₹50 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय बाजार

❑ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए मार्जिन का निर्धारण– अधिकृत डीलर बैंकों को, बैंकों के ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर अपने एफपीआई ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में उनके लेनदेन के लिए मार्जिन निर्धारित करने की अनुमति दी जाए।

❑ जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने वालों द्वारा चलनिधि प्रबंधन में लचीलेपन को सुगम बनाना – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को पात्र निवेशकों को जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने की अनुमति दी जाए। जारीकर्ताओं को चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से सीडी के सभी जारीकर्ताओं को कुछ शर्तों के अधीन परिपक्वता से पहले अपनी सीडी वापस खरीदने की अनुमति दी जाएगी।

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	2
III. विदेशी मुद्रा	3
IV. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
V. अनुसंधान	4
VI. जारी आंकड़े	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जून महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

भुगतान प्रणाली

❑ सप्ताह के सभी दिनों में राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) की उपलब्धता - ग्राहक सुविधा के हित में, और वर्ष के सभी दिनों में आरटीजीएस की उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए, 1 अगस्त 2021 से पूरे वर्ष के सभी दिनों में एनएसीएच उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। पूर्ण विवरण पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी बैठक का कार्यवृत्त

रिज़र्व बैंक ने 18 जून 2021 को 02 से 04 जून 2021 के दौरान आयोजित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की उनतीसवीं बैठक के कार्यवृत्त को सार्वजनिक डोमेन में रखा। एमपीसी के सभी सदस्य - डॉ. शशांक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास - ने सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को अपरिवर्तित रखने तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए मतदान किया। पूर्ण कार्यवृत्त पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों

रिज़र्व बैंक ने 04 जून 2021 को "समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान" पर परिपत्र के तहत निर्दिष्ट सीमा को ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया। परिपत्र उन पात्र उधारकर्ताओं को निर्दिष्ट करता है जिन पर निम्नानुसार समाधान के लिए विचार किया जा सकता है:

❑ जिन व्यक्तियों ने व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिमों का लाभ उठाया है और जिनपर 31 मार्च 2021 तक ऋण देने वाली संस्थाओं का सकल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है।

❑ 31 मार्च 2021 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत के सिवाय खुदरा और थोक व्यापार में लगे कारोबारियों सहित छोटे व्यवसाय जिन पर 31 मार्च 2021 तक उधारदाता संस्थाओं का सकल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

समाधान ढांचा- 2.0: एमएसएमई

रिज़र्व बैंक ने 04 जून 2021 को "समाधान ढांचा 2.0 - एमएसएमई के कोविड-19 संबंधित तनाव का समाधान" पर परिपत्र के तहत निर्दिष्ट सीमा को ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया। परिपत्र में एमएसएमई खातों के लिए पात्रता शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है, जिन्हें ढांचे के तहत पुनर्गठन के लिए विचार किए जाने वाले खातों के तहत पुनर्गठन के लिए विचार किया जाना है, जिसमें कहा गया है कि एमएसएमई उधारकर्ता को सभी उधार संस्थानों के गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित कुल एक्सपोजर 31 मार्च 2021 तक ₹25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए । विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

परामर्शक दस्तावेज़

रिज़र्व बैंक ने 14 जून 2021 को सभी हितधारकों से फीडबैक के लिए माइक्रोफाइनेंस के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया। परामर्शक दस्तावेज के प्रमुख प्रस्तावों की सूची नीचे दी गई है:

❑ सभी विनियमित संस्थाओं के लिए लघु वित्त ऋण की एक समान परिभाषा।

❑ परिवार के ऋण दायित्वों के चुकौती के कारण बहिर्वाह को परिवार आय के प्रतिशत तक सीमित करना।

❑ परिवार के आय के आकलन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति।

❑ कोई पूर्व- भुगतान दंड नहीं; संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं; और सभी लघु वित्त ऋणों के लिए चुकौती आवृत्ति का अधिक लचीलापन।

❑ एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का एनबीएफसी के लिए दिशानिर्देशों के साथ संरेखण।

❑ बेहतर पारदर्शिता के लिए लघु वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण संबंधी एक मानक सरलीकृत तथ्य पत्रक की शुरूआत।

❑ विनियमित संस्थाओं की वेबसाइटों पर लघु वित्त ऋणों पर लगाए गए न्यूनतम, अधिकतम और औसत ब्याज दरों का प्रदर्शन।

परामर्शक दस्तावेज़ पर, टिप्पणियां/विचार/सुझाव बैंकों, एनबीएफसी-एमएफआई सहित एनबीएफसी, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों से 31 जुलाई 2021 तक आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक

स्वर्ण (धातु) ऋण

रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2021 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अधिसूचित किया कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार, सोना आयात करने के लिए अधिकृत नामित बैंक और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 (जीएमएस) में भाग लेने वाले प्राधिकृत बैंक आभूषण निर्यातकों या सोने के आभूषणों के घरेलू निर्माताओं को स्वर्ण (धातु) ऋण (जीएमएल) प्रदान कर सकते हैं। समीक्षा करने के बाद, रिज़र्व बैंक ने निम्नानुसार निर्णय लिया है:

i) बैंक, उधारकर्ता को जीएमएल के एक हिस्से को भौतिक सोने में एक किलोग्राम या उससे अधिक के लॉट में चुकाने का विकल्प प्रदान करेंगे, बशर्ते:

❑ जीएमएल स्थानीय रूप से प्राप्त किए गए / जीएमएस-लिंक्ड सोने से दिया गया है;

❑ पुनर्भुगतान स्थानीय रूप से प्राप्त किए गए आईजीडीएस (इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड) / एलजीडीएस (एलबीएमए गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड) स्वर्ण का उपयोग करके किया जाता है;

❑ बैंक को स्वीकार्य रिफाइनर या केंद्रीय एजेंसी द्वारा उधारकर्ता की ओर से, बिना उसकी भागीदारी के, स्वर्ण सीधे बैंक को सुपुर्द किया जाता है;

❑ ऋण समझौते में उधारकर्ता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विकल्प, स्वीकार्य मानकों और पुनर्भुगतान के लिए स्वर्ण की सुपुर्दगी के तौर-तरीकों का विवरण होता है;
❑ विकल्प का प्रयोग करने के निहितार्थों के बारे में उधारकर्ता को पहले पारदर्शी तरीके से अवगत कराया जाता है।

ii) बैंक उपरोक्त पहलुओं को सहवर्ती जोखिम प्रबंधन उपायों के साथ जीएमएल को नियंत्रित करने वाली बोर्ड-अनुमोदित नीति में उपयुक्त रूप से शामिल करेंगे। बैंक जीएमएल के तहत उधार दिए गए निधि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना जारी रखेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

लाभांश की घोषणा

रिज़र्व बैंक ने 24 जून 2021 को एनबीएफसी द्वारा लाभांश के वितरण पर दिशानिर्देश निर्धारित किए, ताकि अधिक पारदर्शिता और एकरूपता का संचार किया जा सके। दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:
❑ रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी पर दिशानिर्देश लागू होंगे।
❑ 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष और उसके बाद के लाभ से लाभांश की घोषणा के लिए दिशानिर्देश प्रभावी होंगे।
❑ निदेशक मंडल, लाभांश के प्रस्तावों पर विचार करते समय, गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में अंतर पर रिज़र्व बैंक (एचएफसी के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक) के पर्यवेक्षी निष्कर्षों, वित्तीय विवरणों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में अर्हताओं और एनबीएफसी की दीर्घकालिक विकास योजनाएं को ध्यान में रखेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 जून 2021 को निर्णय लिया कि 5000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के आस्ति आकार वाले सभी प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति करेंगे। शहरी सहकारी बैंक इस संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करेंगे:
❑ सीआरओ बैंक के पदानुक्रम में एक वरिष्ठ अधिकारी होगा और उसके पास जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में पर्याप्त व्यावसायिक योग्यता/अनुभव होगा।
❑ सीआरओ को बोर्ड के अनुमोदन से एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा।
❑ बोर्ड सीआरओ की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नीतियां बनाएगा।
❑ सीआरओ का व्यावसायिक कार्यक्षेत्र के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं होगा और उसे कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिया जाएगा।
❑ ऐसे यूसीबी, जो उच्च मूल्य के प्रस्तावों के लिए ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में समिति-पद्धति का पालन करते हैं।
❑ यदि सीआरओ ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में निर्णय लेनेवालों में से एक है, तो उसके पास मतदान की शक्ति होगी और सभी सदस्य जो ऋण स्वीकृति प्रक्रिया का हिस्सा हैं, ऋण प्रस्ताव से संबंधित जोखिम परिप्रेक्ष्य सहित सभी पहलुओं के लिए सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
❑ यूसीबी, जिसमें उच्च मूल्य के ऋणों की मंजूरी के लिए समिति-पद्धति का पालन नहीं होता है, वहाँ सीआरओ मंजूरी प्रक्रिया में केवल एक सलाहकार हो सकता है और उसके पास कोई मंजूरी शक्ति नहीं होगी।
❑ सीआरओ द्वारा सभी ऋण उत्पादों की जांच अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिमों के दृष्टिकोण से की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा

एफपीआई द्वारा मार्जिन का भुगतान

रिज़र्व बैंक ने 04 जून 2021 को भारत में फेमा, 1999 के तहत अधिकृत डीलर श्रेणी -1 लाइसेंस रखने वाले बैंकों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को उनके क्रेडिट जोखिम प्रबंधन ढांचे के अनुसार एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (खजाना बिल और राज्य विकास ऋण सहित) से जुड़े लेनदेन के निपटान के संबंध में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के साथ मार्जिन रखने के उद्देश्य से उधार देने की अनुमति देने का निर्णय लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए , कृपया यहां क्लिक करें।

IV. भुगतान और निपटान प्रणाली

स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) / नकदी रिसाइकलर मशीन

एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान संरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) प्रभारों और शुल्कों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा के लिए जून 2019 को गठित समिति की सिफारिशों की व्यापक जांच के बाद, रिज़र्व बैंक ने 10 जून 2021 को निम्नानुसार निर्णय लिया:
❑ सभी केंद्रों में वित्तीय लेनदेनों के लिए प्रति लेनदेन आदान-प्रदान शुल्क ₹15 से बढ़ाकर ₹17 और गैर-वित्तीय लेनदेनों के लिए इसे ₹5 से बढ़ाकर ₹6 की करने की अनुमति दी गई।
❑ ग्राहक अपने स्वयं के बैंक एटीएम से प्रत्येक महीने पांच निःशुल्क लेनदेनों (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों को मिलाकर) के लिए पात्र हैं। वे अन्य बैंक के एटीएम से निःशुल्क लेनदेनों (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों को मिलाकर) के लिए भी पात्र हैं, अर्थात मेट्रो केंद्रों में तीन लेनदेन और गैर-मेट्रो केंद्रों में पाँच लेनदेन।
❑ यथा लागू कर, यदि कोई हो, अतिरिक्त रूप से देय होंगे।
❑ ये अनुदेश, यथोचित परिवर्तनों सहित, कैश रिसाइकलर मशीनों (नकदी जमा लेनदेनों को छोड़कर) पर किए गए लेनदेनों पर भी लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

बीबीपीएस - बिलर श्रेणी जोड़ना

रिज़र्व बैंक ने 14 जून 2021 को स्वैच्छिक आधार पर, बीबीपीएस में बिलर श्रेणी के रूप में 'मोबाइल प्रीपेड रिचार्जों' की अनुमति प्रदान करने की अनुमति दी। बीबीपीएस बार-बार

किए जाने वाले बिल भुगतानों के लिए एक अंतरपरिचालनीय प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया था जिसमें पाँच श्रेणियों के बिल शामिल थे, अर्थात डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), बिजली, गैस, दूरसंचार और पानी। इस प्रणाली ने मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र, निर्धारित ग्राहक सुविधा शुल्क और कभी भी, कहीं भी डिजिटल भुगतान के विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित किया। बीबीपीएस के दायरे और इसकी व्याप्ति का विस्तार किया गया था, ताकि सभी श्रेणियों के बिलर्स जिनके बिल बार-बार आते हैं (मोबाइल प्रीपेड रिचार्जों को छोड़कर) को स्वैच्छिक आधार पर पात्र प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

V. अनुसंधान

हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना

बैंकिंग हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 03 जून 2021 को 'आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना' शुरू की गई है। भारतीय विश्वविद्यालयों (यूजीसी मान्यता प्राप्त) के कार्यरत/सेवानिवृत्त प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹1,25,000.00 के तीन पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक - समसामयिक पत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2021 को अपने कर्मचारियों के योगदान से अपना समसामयिक पत्र – खंड 41, खंड 2, 2020 प्रकाशित किया। इस शोध-पत्र में चार लेख और दो पुस्तक समीक्षाएं हैं।

लेख:

बैंक पूंजी विनियमों के समष्टि आर्थिक प्रभाव

इस लेख में, श्री रणजॉय गुहा नियोगी और श्री हरेंद्र बेहेरा ने ऋण प्रवाह और जीडीपी वृद्धि को प्रभावित करने में विनियामक बैंक पूंजी की भूमिका की जांच की। पूरा लेख पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

तमिलनाडु में शिक्षा ऋण एनपीए: मुद्दे और चुनौतियां

इस लेख में, सुश्री श्रोमोना गांगुली और सुश्री दीपा एस. राज ने तमिलनाडु में शिक्षा ऋण में चूक के निर्धारकों का अध्ययन किया है। वे दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक के लगभग दो लाख उधारकर्ताओं के खाता स्तर के डेटा का उपयोग, चूक के महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता की पहचान करने के प्रयास में करते हैं। पूरा लेख पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

कोर मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के लिए आर्थिक सुस्ती का एक वैकल्पिक उपाय

इस लेख में, श्री सौरभ शर्मा और सुश्री इप्सिता पाधी विभिन्न प्रकार के उच्च आवृत्ति संकेतकों का उपयोग करके आर्थिक सुस्ती का एक वैकल्पिक संकेतक प्रस्तावित करते हैं। पूरा लेख पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

दीर्घकालिक बचत - भारत में निवेश संबंध

इस लेख में, श्री बिचित्रानंद सेठ, श्री कुणाल प्रियदर्शी और श्री अवधेश कुमार शुक्ला ने फेल्डस्टीन-होरियोका पहेली, अर्थात सीमा पार पूंजी प्रवाह के लिए बढ़ते खुलेपन के बावजूद घरेलू बचत और निवेश दरों के बीच घनिष्ठ संबंध, जो अब भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों में पकड़ रखता है, पर फिर से विचार किया। पूरा लेख पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

पुस्तक समीक्षाएं:

श्री रसमी रंजन बेहरा ने बेन एस बर्नानके, टिमोथी एफ. गेथनर और हेनरी एम. पॉलसन, जूनियर द्वारा लिखित पुस्तक "फायरफाइटिंग: द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इट्स लेसन" की समीक्षा की। यह पुस्तक 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और इसके प्रबंधन के तरीके पर उत्कृष्ट वर्णन प्रदान करती है। पूरी पुस्तक समीक्षा पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

सुश्री प्रियंका उप्रेती ने सीमा बथला, प्रमोद कुमार जोशी और अंजनी कुमार द्वारा लिखित पुस्तक "एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया" की समीक्षा की। पुस्तक ने कृषि में सार्वजनिक और निजी निवेश के बीच संबंधों को मापा है और कृषि उत्पादकता, आय और गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव का आकलन किया है। पूरी पुस्तक समीक्षा पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VI. जारी आंकड़े

जून 2021 माह में रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए:

	जारी आंकड़े
1	अप्रैल 2021 माह के लिए भारत के अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
2	भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए
3	मई 2021 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
4	2020-21 की चौथी तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)
5	दिसंबर 2020 के अंत में घरेलू ऋण-जीडीपी अनुपात और 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए घरेलू वित्तीय बचत के प्रारंभिक अनुमान
6	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा "तिमाही बीएसआर-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण – मार्च 2021" जारी किया गया
7	वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की गतिविधियां
8	2020-21 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन के स्रोत

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।